

मुख्यमंत्री ने सांगानेर को दी 631 करोड़ रु. के 1538 विकास कार्यों की सौगात

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 4 जुलाई को जयपुर मेट्रो फेज-2 परियोजना का शिलान्यास करेंगे : भजनलाल शर्मा

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशभर में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ नागरिक सेवाओं के विस्तार पर प्राथमिकता से कार्य कर रही है। सरकार का उद्देश्य अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना और आमजन को बेहतर जीवन सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री बुधवार को सांगानेर स्टेडियम में आयोजित लगभग 631 करोड़ रुपये की लागत के 1538 विकास कार्यों के लोकार्पण, शिलान्यास एवं पट्टा वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन विकास कार्यों से सड़क, पेयजल, सीवेज, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और उन्नयन होगा, जिससे क्षेत्र के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिल सकेंगी।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को सांगानेर स्टेडियम में 631 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया।

- जयपुर-भीलवाड़ा रोड स्थित मुहाना मोड जंक्शन पर 124 करोड़ रुपये की लागत से प्लाईओवर बनेगा
- बंबाला क्षेत्र में 88 करोड़ रुपये से अधिक लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), पृथ्वीराज नगर में सैटेलाइट अस्पताल तथा भांकरोटा में टूट्टा सेंटर निर्माण की नींव रखी
- राजधानी की संकरी गलियों में सफाई के लिए 5 अत्याधुनिक "मैकेनिकल लिटर पिकर मशीनें" जयपुर नगर निगम को सौंपी

के समग्र शहरी विकास को नई गति मिलेगी। यह परियोजना भविष्य की बढ़ती आबादी और यातायात की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जयपुर-भीलवाड़ा रोड स्थित मुहाना मोड जंक्शन

पर 124 करोड़ रुपये की लागत से प्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा बंबाला क्षेत्र में 88 करोड़ रुपये से अधिक लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), पृथ्वीराज नगर में सैटेलाइट अस्पताल तथा

भांकरोटा में टूट्टा सेंटर निर्माण की आधारशिला रखी गई। सांगानेर के 115 मंदिरों के सौंदर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार कार्य का भी शुभारंभ किया गया है। इसके अलावा यूनिटी मॉल, रिडि-सिडि प्लाईओवर, सांगानेर एलिवेटेड

रोड और द्रव्यवती नदी विकास जैसे महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी प्रगति पर हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में पहली बार जयपुर नगर निगम के लिए पांच अत्याधुनिक मैकेनिकल लिटर पिकर मशीनें लाई गई हैं। ये मशीनें फुटपाथों, संकरी गलियों और ट्रांसफार्मरों के नीचे जमा कचरे को भी प्रभावी ढंग से साफ करने में सक्षम होंगी।

समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने सीवरेज सफाई के लिए सुपर स्कर मशीन और स्वच्छ सर्वेक्षण-2026 के प्रति जनजागरूकता के लिए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही, सफाई सेवा मैरथन के विजेताओं को चेक भी वितरित किए।

मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड वितरित करते हुए कहा कि स्वामित्व योजना ड्रोन तकनीक के माध्यम से गांवों की आवासीय भूमि का सीमांकन कर ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का कानूनी स्वामित्व प्रदान करने में बेहद उपयोगी साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 8 हजार से अधिक गांवों का ड्रोन सर्वेक्षण कर लगभग 14 लाख स्वामित्व कार्ड जारी किए जा चुके हैं। समारोह में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, नगरीय विकास एवं स्वास्थ्य शासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा, सांसद मंजू शर्मा, विभिन्न जनप्रतिनिधि, अधिकारी तथा बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

राजसमंद-सिरोही में फार्मर रजिस्ट्री आधारित उर्वरक वितरण प्रणाली होगी लागू

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण तथा उर्वरक विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार एग्रीस्टेक योजना के अंतर्गत जारी फार्मर रजिस्ट्री का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय उर्वरक तंत्र के तहत प्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल्स लागू किया जा रहा है।

- अनुदानित उर्वरकों के वितरण में बढ़ेगी पारदर्शिता, किसानों को मिलेगा सीधा लाभ
- प्रदेश में 86.66 लाख किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा चुकी है, इस कार्य में राजस्थान देश के अग्रिणी राज्यों में शामिल : कृषि आयुक्त

रोकने के लिए इस अभिनव पहल को राजस्थान में प्रथम चरण में सिरोही एवं राजसमंद जिलों में पायलट परियोजना के रूप में 25 जून से लागू किया जा रहा है। इस प्रणाली के माध्यम से किसानों को अनुदानित उर्वरकों का विवरण अधिक पारदर्शी, प्रभावी एवं डिजिटल माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री आधारित एफएफएस प्रणाली लागू होने से वास्तविक

बाद कृषक नजदीकी उर्वरक डीलर से अनुदानित उर्वरक ले सकेंगे।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में 86.66 लाख किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा चुकी है। फार्मर आईडी बनाने में राजस्थान देश के अग्रिणी राज्यों में शामिल है। इस पहल के सफल क्रियान्वयन हेतु चयनित जिलों में आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके तहत ब्लॉक एवं ग्रामवार कार्यरत खुदरा उर्वरक विक्रेताओं की जानकारी का एलजीडी कोड सहित पोर्टल पर अपडेट करना, मास्टर ट्रेनर्स की पहचान, प्रचार-प्रसार सामग्री तैयार करना तथा उर्वरक विक्रेताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने जैसे महत्वपूर्ण गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसके साथ ही चयनित जिलों में उर्वरकों के स्टॉक एवं उपलब्धता की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर

जारी दिशा-निर्देशों को प्रभावी पालना सुनिश्चित की जाएगी। कृषि आयुक्त ने कहा कि यह पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल गवर्नंस को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे किसानों को समय पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी तथा सरकारी अनुदान का लाभ वास्तविक ग्राहक किसानों तक पहुंचाने में सहायता मिलेगी।

ने बताया कि भारत सरकार द्वारा उर्वरकों पर भारी सब्सिडी प्रदान की जाती है। अनुदानित उर्वरकों का गैर कृषि कार्यों में उपयोग, कालाबाजारी, जमाखोरी आदि आपराधिक कृत्यों को

उन्होंने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री आधारित एफएफएस प्रणाली लागू होने से वास्तविक

बाद कृषक नजदीकी उर्वरक डीलर से अनुदानित उर्वरक ले सकेंगे।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में 86.66 लाख किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा चुकी है। फार्मर आईडी बनाने में राजस्थान देश के अग्रिणी राज्यों में शामिल है। इस पहल के सफल क्रियान्वयन हेतु चयनित जिलों में आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके तहत ब्लॉक एवं ग्रामवार कार्यरत खुदरा उर्वरक विक्रेताओं की जानकारी का एलजीडी कोड सहित पोर्टल पर अपडेट करना, मास्टर ट्रेनर्स की पहचान, प्रचार-प्रसार सामग्री तैयार करना तथा उर्वरक विक्रेताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने जैसे महत्वपूर्ण गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसके साथ ही चयनित जिलों में उर्वरकों के स्टॉक एवं उपलब्धता की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर

जारी दिशा-निर्देशों को प्रभावी पालना सुनिश्चित की जाएगी। कृषि आयुक्त ने कहा कि यह पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल गवर्नंस को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे किसानों को समय पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी तथा सरकारी अनुदान का लाभ वास्तविक ग्राहक किसानों तक पहुंचाने में सहायता मिलेगी।

नम्बर मिलाइए 8890333139

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

पावरग्रिड POWERGRID

सूचना

1. ऊपर बताए गए याचिकाकर्ता ने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलटरी कमीशन, नई दिल्ली के सामने याचिका-1 (उत्पत्ती क्षेत्र में 400 केवी ट्रांसमिशन लाइनों पर रिफ़ेक्टिव पावर कम्पेन्सेशन) के लिए 2024-29 टैरिफ ब्लॉक के ट्रांसमिशन टैरिफ तय करने के लिए एक याचिका दायर की है।

2. ट्रांसमिशन सिस्टम से फायदा उठाने वाले से है: (क) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (ख) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (ग) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (घ) जयपुर टैरिफ इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड ड.) हरियाणा पावर परफेक्ट सेंट्र (म) जम्मू-कश्मीर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (न) उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (द) बीएसएलएन एमएन पावर लिमिटेड (र) बीएसएलएन राजधानी पावर लिमिटेड (ड) टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (ड) बंसीगढ़ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट (ड) उत्तरांचल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ण) नॉर्थ सेंट्रल रेलवे (न) नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (ह) हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (र) सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (ए) एचबीपीएनएल

वितरण

व्यावसायिक संचालन की निर्धारित तिथि	13.01.2024
व्यावसायिक संचालन की वास्तविक तिथि	30.06.2025 (परिसर्पति-1)
	22.10.2025 (परिसर्पति-2)
	20.03.2026 (परिसर्पति-3)
	25.04.2026 (परिसर्पति-4)

पूरा होने की अनुमानित लागत (लाख रुपये में)

	83.92 करोड़
--	-------------

3. 2024-29 ब्लॉक के लिए टैरिफ का विवरण: (लाख रुपये में)

परिसर्पति	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
परिसर्पति-1	105.38	224.58	229.80	229.85	
परिसर्पति-2	-	55.49	158.07	201.04	215.78
परिसर्पति-3	-	16.54	534.45	581.12	596.97
परिसर्पति-4	-	-	277.45	338.26	357.19

4. टैरिफ के निर्धारण हेतु दायर याचिका की एक प्रति वेबसाइट www.powergrid.in पर उपलब्ध है।

5. याचिका में निहित टैरिफ निर्धारण के प्रस्तावों पर यदि किसी व्यक्ति, जिसमें लाभार्थी भी शामिल हैं, को कोई सुझाव अथवा आपत्तियां प्रस्तुत करनी हों, तो वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर आयोग के ई-पोर्टल के माध्यम से, उसकी एक प्रति याचिकाकर्ता को प्रेषित करते हुए, दाखिल कर सकते हैं।

स्थान: गुरुग्राम हरियाणा / -
दिनांक: 25.06.2026 सचिव महाप्रबंधक (वाणिज्यिक-सीसी)

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय: बी-9, कृष्ण इस्टीमेटेशन परिसर, कटवाली सराय, नई दिल्ली-110016
केन्द्रीय कार्यालय: 'सौभाग्य', प्लॉट नं.-2, सेक्टर-29, गुरुग्राम, हरियाणा-122001
वेबसाइट: www.powergrid.in, सीआईएन: L40101DL1989GQI38121
एक महारत्न उद्यम

देवनाली ने लेह लद्दाक में प्रथम सिंधु कुंभ में पूजा-अर्चना

जयपुर। लेह-लद्दाक में आयोजित प्रथम सिंधु कुंभ राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक समरसता और आध्यात्मिक चेतना का विराट मंच बनकर उभरा। देशभर के लगभग 20 राज्यों से आए 3500 से अधिक श्रद्धालुओं, संत-महात्माओं और सामाजिक प्रतिनिधियों की सहभागिता से सिंधु नदी का तट 'लघु भारत' का जीवंत प्रतिबिंब नजर आया। राजस्थान से भी करीब 500 श्रद्धालु इस ऐतिहासिक आयोजन में शामिल होने लेह-लद्दाक पहुंचे।

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनाली ने पवित्र सिंधु घाट पर मां सिंधु नदी और भगवान झूलाल की विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर देश, प्रदेश और समाज की सुख-समृद्धि, शांति एवं प्रगति की कामना की। देवनाली ने कहा कि सिंधु नदी केवल एक जलधारा नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति और राष्ट्रीय अस्मिता की अमर प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सिंधु तट का संबंध वेदों और उपनिषदों की रचना से रहा है और भारतीय ज्ञान परंपरा के विकास में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। भगवान झूलाल का

अवतरण भी इसी पवित्र नदी के तट पर हुआ, जिन्होंने मानवता, प्रेम, सद्भाव, सेवा, जल संरक्षण और लोककल्याण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सिंधु तट पर श्रद्धा, संस्कृति और राष्ट्रीय एकता का जो अद्भुत संगम दिखाई देता है, वह भारत की सनातन परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का सशक्त परिचायक है। सिंधु नदी का यह पावन तट अब भारतीय सभ्यता, संस्कृति और राष्ट्रीय अस्मिता के साथ-साथ आध्यात्मिक दृष्टि से देश के पांचवें धाम के रूप में विकसित होता जा रहा है। बुधवार को आयोजित प्रथम सिंधु कुंभ में देशभर से जुटे हजारों श्रद्धालुओं ने भारत की विविधता में एकता की भावना को साकार किया। विभिन्न भाषाओं, परंपराओं और संस्कृतियों से जुड़े लोग एक ही मंच पर एक सूत्र में बंधे नजर आए।

आयोजन में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक डेनरेश कुमार, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, त्रिपुरा विधानसभा अध्यक्ष रामपदा जमातिहा सहित विभिन्न क्षेत्रों के अनेक जिज्ञात उपस्थित रहे।

"लोकतंत्र की हत्या का काला अध्याय" विषय पर भाजपा की संगोष्ठी आज

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी की ओर से 25 जून को "लोकतंत्र की हत्या का काला अध्याय" विषय पर एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम संयोजक एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने बताया कि कार्यक्रम गुरुवार प्रातः 10 बजे दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र के सभागार में आयोजित होगा। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उपस्थित रहेंगे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठी

करेंगे। 25 जून भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक ऐसा दिन है, जिसे देश कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने देश में आपातकाल लागू कर लोकतांत्रिक संस्थाओं, संविधान प्रदत्त अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन किया गया था। लाखों प्रचारकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेलों में बंद किया गया तथा प्रेस पर सेंसरशिप लगाकर नागरिक स्वतंत्रताओं को कुचलने का प्रयास किया गया।

पशुपालन मंत्री ने ब्यावर से किया लम्पी टीकाकरण अभियान का आगाज

पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने गोवंश को लम्पी स्किन डिजीज से सुरक्षित रखने के लिए राज्य स्तरीय टीकाकरण अभियान का बुधवार को आगाज किया।

जयपुर। पशुपालन, डेयरी एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने गोवंश को लम्पी स्किन डिजीज (एलएसडी) से सुरक्षित रखने हेतु राज्य स्तरीय टीकाकरण अभियान का बुधवार को आगाज किया।

कुमावत ने श्री तिजारती सर्राफान चैम्बर गौशाला, ब्यावर में गोवंश को टीके लगवाए। कार्यक्रम के दौरान पशुपालन विभाग के 11 पशु परिचर, 38 पशुधन निरीक्षक, 16 पशु चिकित्सा अधिकारियों ने गौशाला में मौजूद 773 गोवंशीय पशुओं (272 नर एवं 501 मादा) का टीकाकरण किया। कुमावत ने लम्पी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण को अत्यंत आवश्यक बताया। उन्होंने उपस्थित पशुपालकों को राज्य सरकार द्वारा पशुधन संरक्षण एवं पशुपालकों के हित में संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि दो वर्ष पूर्व लम्पी रोग के लिए पृथक वैकसीन उपलब्ध नहीं होने के कारण गोट पॉक्स वैकसीन का उपयोग किया गया था, जिससे पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हुई। अब लम्पी रोग के लिए विशेष वैकसीन उपलब्ध होने से अभियान को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। राज्य में वर्ष 2025-26 के दौरान

108.95 लाख गोवंशीय पशुओं का टीकाकरण किया गया था। वर्ष 2026-27 के लिए 111.51 लाख पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ब्यावर जिले में वर्ष 2026-27 के दौरान 1 लाख 23 हजार 936 गोवंशीय पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के अंतर्गत होमोलॉगस रॉची स्ट्रेन लाइव एटेन्यूएटेड वैकसीन का उपयोग किया जा रहा है।

ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत ने कहा कि लम्पी स्किन डिजीज टीकाकरण अभियान के राज्य स्तरीय शुभारंभ का ब्यावर से होना जिले के लिए गौरव और सौभाग्य की बात है। राज्य सरकार के लिए भारत माता, धरती माता और गौ माता की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। रावत ने गौसेवा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र

में नई गौशालाओं के संचालन एवं विस्तार की आवश्यकता पर बल देते हुए अपनी मांग रखी, जिस पर श्री कुमावत ने सकारात्मक रैस्पॉस दिया। पशुपालन निदेशक डॉ. सुरेश चन्द मीणा ने कहा कि विभाग राज्य सरकार की मंशानुसार सभी योजनाओं को प्रभावी रूप से धरातल तक पहुंचाने तथा विभागीय लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध है। अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्र), पशुपालन विभाग अजमेर डॉ. नवीन परिहार ने बताया कि एलएसडी एक संक्रामक वायरल रोग है, जो मुख्य रूप से गोवंशीय पशुओं को प्रभावित करता है। अजमेर संभाग की समस्त गौशालाओं में गौवंश का प्राथमिकता से टीकाकरण सुनिश्चित करने हेतु सभी जिला संयुक्त निदेशकों एवं उपनिदेशकों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

कार्यक्रम के उपरांत गौशाला परिसर में अतिथियों द्वारा पौधारोपण किया गया तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में पूर्व सभापति नरेश कनोजिया, अतिरिक्त कलक्टर ब्रह्मलाल जाट, पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, गौशाला अध्यक्ष, गौशाला संचालक, गौसेवक, जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

बैरियर रहित टोल प्रणाली

एनएच-48 के दिल्ली-जयपुर खंड पर स्थित दौलतपुरा टोल प्लाज़ा पर लागू

हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने की दिशा में बहुत बड़े कदम उठाए हैं, दूसरी तरफ सामान्य मानव के जीवन में जो बाधाएँ हैं, ईज़ ऑफ लिविंग का जो हमारा सपना है, उस पर भी हमने उतना ही बल दिया है।

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

अब टोल पर न रुकावट, न इंतज़ार

राजमार्ग यात्राएं अब सुगम, निर्बाध और प्रौद्योगिकी संचालित

लाभ

- टोल पर प्रतीक्षा नहीं
- समय की बचत
- ईंधन की बचत
- प्रदूषण में कमी
- सुगम जीवन और व्यापार करने में सुगमता

बिना रुकावट टोल भुगतान के लिए

- अपने FASTag को पर्याप्त बैलेंस के साथ सक्रिय रखें और उसे विडस्क्रीन पर सही तरीके से लागू करें
- अपर्याप्त बैलेंस या अमान्य FASTag होने पर दोगुनी टोल राशि का ई-नोटिस जारी किया जाएगा
- ई-नोटिस जारी होने पर वाहन की FASTag सेवाएं निरालंबित कर दी जाएगी
- ई-नोटिस देखने और भुगतान के लिए NIC पोर्टल <https://nhfeenotice.parivahan.gov.in/> पर जाएं
- यदि 72 घंटे के भीतर भुगतान नहीं किया गया, तो सामान्य टोल दर से दोगुना शुल्क लिया जाएगा
- यदि कोई शिकायत हो, तो उपयोगकर्ता NIC पोर्टल पर दर्ज करा सकता है
- ई-नोटिस का भुगतान न करने पर संबंधित वाहन सेवाओं जैसे एनओसी, स्वामित्व हस्तांतरण, फिटनेस सर्टिफिकेट और नेशनल परमिट आदि पर प्रतिबंध लग सकता है
- अपने वाहन पर केवल साफ, स्पष्ट और मानकीकृत नंबर प्लेट (हाई सिक्वोरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) का ही उपयोग करें

सड़कें ही नहीं, राष्ट्र का निर्माण भी